सरकार से वार्ता के आश्वासन के बाद चौकीदारों का महापड़ाव खत्म

करनाल। सेक्टर-12 स्थित पार्क में ग्रामीण चौकीदारों का महापड़ाव दूसरे दिन भी जारी, लेकिन मांगों को लेकर चौकीदारों के प्रतिनिधि मण्डल से सीएम से मुलकात का समय मिलने के बाद चौकीदारों ने महापड़ाव समाप्त कर दिया। मांगों को लेकर दो दिन से पार्क के शेड के नीचे चौकीदार डेरा डालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहे। चौकीदारों का कहना है कि पिछले काफी समय से वह अपनी मांगें पूरी कराने के लिए अधिकारियों से लेकर सत्तासीनों को ज्ञापन दे चुके है। परन्तु उन्हें आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला। सरकार ने आज तक उनकी मांग पूरी नहीं की, जिस कारण विवश होकर उन्हें आंदोलन का रास्त चुनने पड़ा। चौकीदारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वह बड़ा आंदोलन छेडने से पीछे नहीं हटेंगे।

दो दिन के महापड़ाव में चौकीदार सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते रहे। चौकीदारों के प्रदर्शन के आज दूसरे दिन प्रशासन ने आंदोलनरत चौकीदारों को सरकार से वार्ता का भरोसा दिलाकर उनसे 5 सदस्य प्रतिनिधि मण्डल के चण्डीगढ़ जाकर बातचीत कराने का समय तक करा दिया। चौकीदारों ने मांग की कि उनको 24 हजार रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। जिन गांवों में जनसंख्या अधिक है, वहां पर चौकीदारों की संख्या बढ़ाई जाए और 6 माह में वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाए। कोरोना की चपेट में आने से मौत होने पर चौकीदार को 20 लाख रुपए बीमा राशि व परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए।

देखना है कि अब चौकीदारों के साथ सरकार से वार्ता के बाद कौन सी मांगें मानी जाएगी तथा चौकीदार सरकार से कितने संतुष्ट होंगे।

शहीद भगत सिंह को आतंकवादी बताने पर सिमरनजीत मान के खिलाफ केस दर्ज करने पर शांडिल्य ने दिया गृह मंत्री विज को ज्ञापन

करनाल। एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को ज्ञापन दिया और शहीद भगत सिंह को आंतकवादी बताने वाले संगरूर के सांसद एव खलिस्तानी मुहिम चलाने वाले सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शांडिल्य ने गृह मंत्री अनिल विज को दिए ज्ञापन में कहा कि शहीद-ए-आजम भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले सिमरनजीत मान ने हरियाणा व देश की सुरक्षा व अंतरिम सुरक्षा को साजिश के तहत खंडित करना चाहा।

शहीद भगत सिंह क्रांतिकारी थे और उन्होंने अंग्रेजी हकूमत को ललकारते हुए और हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमा ओर देश को आजादी दिलाने के लिए शहादत दी। शांडिल्य ने गृह मंत्री अनिल विज को सौपे ज्ञापन में कहा कि देश की 132 करोड़ जनता की भावनाओं का सिमरनजीत सिंह ने भगत सिंह को आतंकवादी बताकर भड़काया व भगत सिंह को हरियाणा के पौने तीन करोड़ लोगों मे बदनाम किया और प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश रची।

यदि भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले सिमरनजीत मान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल में न डाला गया तो क्रांतिकारियों का अपमान होगा । गृह मंत्री अनिल विज ने वीरेश शांडिल्य को आश्वासन दिया कि क्रांतिकारी शहीद ए आजम भगत सिंह को आतंकवादी बताने वाले सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और वो गिरफ्तार भी होगा और उन्होंने कहा की सिमरनजीत मान जैसे लोगों को ना हरियाणा की शांति भंग करने देंगे ना शहीदों का अपमान करने देंगे। उन्होंने शांडिल्य की इस शहीदों के प्रति सोच का स्वागत भी किया ।

भाजपा विपक्ष को कुचलने का कर रही है प्रयास : ललित बुटाना

कांग्रेस अध्यक्ष के साथ हुए व्यवहार को बताया शर्मनाक

करनाल। कांग्रेस पार्टी के नेशनल ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य ललित बुटाना ने स्मृति ईरानी का कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ व्यवहार शर्मनाक बताया है। वह स्तब्ध हैं कि कैसे सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भाजपा के सांसदों ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ अनावश्यक नारेबाजी की। स्मृति ईरानी का व्यवहार ठीक नहीं था वह सोनिया गांधी की बराबरी नहीं कर पाएंगी।

उन्होंने कहा कि बीजेपी विपक्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। वह आज अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। गत दिवस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई केन्द्रीय मंत्री सुमृति ईरानी ने देश के समक्ष महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी जैसे ज़रूरी मुद्दों पर बहस को रोक कर राष्ट्रपति के उच्चारण को बेवजह का मुद्दा बनाने की कोशिश की तथा कांग्रेस अध्यक्षा को मानसिक व शारीरिक चोट पहुँचाने के लिए बीजेपी के सांसदों को सोनिया गांधी के खिलाफ उकसाया व भड़काया जो कि बहुत निंदनीय है।

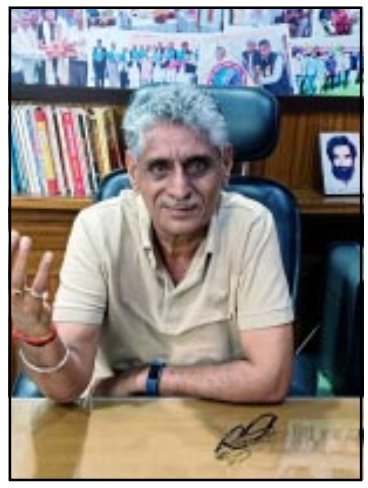

सोनिया गांधी ने देश को नई दिशा देने में निभाई सकारात्मक भूमिका : कांग्रेस नेता ने कहा कि सोनिया गांधी ना केवल कांग्रेस अध्यक्ष हैं अपितु वह देश की ऐसी नेता हैं जिन्होंने सास और पति की हत्या के बाद खुद को संभालते हुए देश को नई दिशा देने में सकारात्मक काम किया और हमेशा मर्यादित व मूल्य आधारित राजनीति की है।

देश की जनता देगी बीजेपी को माकूल जवाब : ललित बुटाना ने कहा कि आज देश की जनता जागरूक है वह बीजेपी द्वारा किए जा रहे तमाशे को पैनी नजर से देख व महसूस कर रही है जिसका समय आने पर बीजेपी को माकूल जवाब जनता स्वयं देगी। मामला बहुत ही साधारण था कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद अधीर रंजन चौधरी जो कि बंगाल से आते हैं तथा हिन्दी उच्चारण में त्रुटि हो जाने के कारण राष्ट्रपति जी को सही से राष्ट्रपति नहीं कह पाये जिसके लिए उन्होंने तुरंत स्पष्टीकरण भी दिया व राष्ट्र अध्यक्ष के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त किया। बीजेपी के इस अभद्र व्यवहार से निश्चित तौर पर लोकसभा की गरिमा को ठेस पहुँची है उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी पर भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा की सांसद रमा देवी के पास जाकर कौन सा अपराध कर दिया, ऐसा तो सदन में होता रहता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य कार्यवाही स्थगित होने के बाद मिलते जुलते और बात करते हैं। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हुई यह ठीक नहीं था।

करनाल जिले में 85 अवैध कॉलोनियों को किया चिन्हित, जल्द होगी कार्रवाई

करनाल। टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग की 2011 की अधिसूचना के तहत गठित जिला टास्क फोर्स की बुधवार को एडीसी डॉ. वैशाली शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मीटिंग में करनाल के डीटीपी आर.एस. बाठ ने बताया कि जिला में 80 से 85 ऐसी कॉलोनियां का पता लगाया गया है, जो अवैध हैं और प्रारम्भिक स्टेज पर हैं। इनमें से करीब 40 कॉलोनियां अकेले करनाल अर्बन में हैं। इसे देखते लोगों से अपील की जाती है कि वे अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें। उन्होंने बताया कि इस बारे सभी उपमण्डलाधीशों व तहसीलदारों को किला नम्बर/खसरा नम्बर सहित लिखित सूचना भेजी जा रही है कि वे ऐसी कॉलोनियों में रजिस्ट्री न करें। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को ऐसी कॉलोनियों की लोकेशन देकर उनसे भी इनमें कनैक्शन न देने के लिए अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनता की जानकारी के लिए ऐसी कॉलोनियों की सूची, उपायुक्त कार्यालय, नगर निगम, सभी एसडीएम कार्यालय व तहसीलों में चस्पा करवाई जाएंगी। अवैध कॉलोनियों क्यों डव्ल्प हो रही हैं, इसे रोकने के लिए डीटीपी ने मीटिंग में मौजूद अधिकारियों से सुझाव भी मांगे।

मीटिंग में डीटीपी ने बताया कि करनाल का वर्ष 2025 तक का मास्टर प्लान बना हुआ है। भविष्य को देखते हुए इसमें जल्द ही नई चीजें जोड़कर इसे 2041 तक का बनाएंगे, जिसमें कंट्रोल्ड एरिया को घोषित किया जाएगा। कंट्रोल्ड एरिया में किसी भी तरह की डव्ल्पमेंट के लिए परमिशन लेनी अनिवार्य होती है।

रजिस्ट्री के लिए तहसीलदार को 1 एकड़ से कम जगह की एनओसी लेनी जरूरी- उन्होंने बताया कि कंटोल्ड और अर्बन एरिया में कुछ ऐसे एरिया हैं, जिसमें कोई भी तहसीलदार 7-ए के तहत रजिस्ट्री कर सकता है, लेकिन एक एकड़ से कम जगह के लिए डीटीपी से एनओसी लेनी अनिवार्य है, 7-ए, हरियाणा डव्ल्पमेंट एंड रेगूलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 में आता है।

उन्होंने बताया कि आर.डब्ल्यू.ए. और लाईसेंसियों की ओर से कुछ कॉलोनियों में डव्ल्पर्स द्वारा सुविधाएं न देने को लेकर जिला प्रशासन को शिकायतें मिलती रहती हैं। इन्हें दूर करने के लिए डीटीपी कार्यालय, आर.डब्ल्यू.ए. के साथ नियमित तौर पर बैठकें कर रहे हैं। अब तक 5 बैठकें की जा चुकी हैं। निर्णय लिया गया है कि हर 2 महीने में ऐसी बैठकें की जाएंगी। उन्होंने बताया कि आर.डब्ल्यू.ए., कॉलोनियों में सड़के न होने, एसटीपी का न होना और मेन रोड या हाईवे से उपयुक्त रास्ता न मिलने जैसे मुद्दों को लेकर प्रशासन के पास आते हैं।

डीटीपी ने बताया कि सरकार की 19 जुलाई 2021 की पॉलिसी के अनुसार नगर निगम एरिया के बाहर जो भी अवैध कॉलोनी है और जो 1 जुलाई 2022 के पहले की बनी है, उसे नियमित करवाने के लिए, जिला स्तरीय गठित कमेटी को आवेदन किया जा सकता है। उपायुक्त इस कमेटी के चेयरमैन तथा डीटीपी सदस्य सचिव हैं। जिला परिषद के सीईओ, डीडीपीओ, लोक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग तथा पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता, वन मंडल अधिकारी और तहसीलदार बतौर मैम्बर कमेटी में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे आवेदन के प्रस्तावों को आगामी कार्रवाई के लिए मंडल आयुक्त के पास भेजा जाएगा। इस पॉलिसी में जितने भी बिन्दू शामिल हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक किया जाएगा।

अवैध कॉलोनियों को लेकर जनता दे सकती है सुझाव, डीटीपी कार्यालय में लगाई सुझाव पेटी- उन्होंने बताया कि अवैध कॉलोनियों को पनपने न देने के लिए जनता भी अपने सुझाव दे सकती है। इसके लिए डीटीपी कार्यालय में सजैशन बॉक्स लगाया गया है। लोग चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपने उपयोगी सुझाव दे सकते हैं।

मीटिंग में डीटीपी ने एडीसी के समक्ष अवैध निर्माण की तोड ?ोड़ करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल आवश्यकता की मांग उठाई और कहा कि ऐसी मुहिम में 20 से 25 पुलिस कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है, पुलिस लाईन से मिल जाएं तो अच्छा है। इस पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में जो भी डैमोलिशन ड्राईव करनी हों, उसकी एंडवांस सूचना या शैड्यूल एस.पी. कार्यालय को दे दें, ताकि समय पर उचित पुलिस बल का बंदोबस्त किया जा सके। करनाल पुलिस को लेकर उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि बीते 2 सालों में पुलिस को कार्रवाई के लिए जितना लिखा गया है, उसमें से 90 प्रतिशत प्राथमिकी दर्ज हुई हैं।

डीटीपी ने बताया कि अल्फा सिटी, सीएचडी सिटी व असंल जैसी जितनी भी लाईसेंसी कॉलोनियां हैं, यदि कोई व्यक्ति इन कॉलोनियों के आवासीय एरिया में व्यवसायिक गतिविधि करना चाहता है, तो वह अनुमति लेकर 50 वर्ग मीटर में कर सकता है। इसके लिए सम्बंधित व्यक्ति को 5 साल की अवधि के लिए 30 हजार रूपये की फीस जमा करवानी होगी।

उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशानुसार करनाल जिला में 144 कॉलोनियों का ड्रोन से सर्वे करवाया गया है। इनमें 45 कॉलोनी ऐसी हैं, जो नगर पालिका/नगर निगम से बाहर हैं, बाकी अंदर हैं। सर्वे का मकसद उन्होंने बताया कि ऐसी कॉलोनियों में तोडफ़ोड़ से पहले यह देखा जाएगा कि इसमें कितने मकान बने हुए हैं।